आपरेशन फ्लड-3 के अंतर्गत गुजरात की परियोजनाओं को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	लाख रुपयों में
1992-93	3479.42
1993-94	14014.86
1994-95(जून, 1994 तक)	330.00

(ग) गुजरात राज्य में स्थापित की जाने वाली संभावित डेरी विकास परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

गुजरात में स्थापित की जाने वाली संभावित डेरी परियोजनाएं

ब्यौरा	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	पूरी होने की संभावित तारीख
मेहसाना डेरी सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड		
1. मेहसाना डेरी का विस्तार चरण-3	844	दिसंबर, 94
2. हंसापुर प्रशीतन केन्द्र का विस्तार	123	दिसंबर, 95
3. काडी प्रशीतन केन्द्र का विस्तार	123	दिसंबर, 95
सूरत जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड		
1. सूरत डेरी का विस्तार	122	जनवरी, 95
2. उच्छल प्रशीतन केन्द्र का विस्तार	34	मार्च, 95
3. नदी परादी प्रशीतन केन्द्र	397	फरवरी, 96
कुल	1643 लाख	

डेरी क्षेत्र का उदारीकरण

2456. **श्री सुरेश पचौरी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के केन्द्र सरकार द्वारा डेरी क्षेत्र को उदारीकरण नीति के दायरे में लाये जाने का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्यक्ष ने यह कहा है कि बहुराष्ट्रिक कंपनियों को अपनी डेरी इकाइयां स्थापित करने की अनुमति देने और उन्हें किसानों की कई वर्षों की कड़ी मेहनत के कारण स्थापित हुए ढांचे का लाभ उठाने में मदद देने का कोई औचित्य नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कहा गया है कि बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को कई वर्षों में स्थापित हुए इस आधारभूत ढांचे को प्राप्त कर लेने का कोई अधिकार नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार डेरी क्षेत्र को उदारीकरण नीति के दायरे में न लाने पर विचार कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी हां। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष ने भारत में डेरी क्षेत्र को लाइसेंस से मुक्त करने के तरीके का विरोध किया है। उनका मानना है कि लाइसेंस को समाप्त करने का सिद्धान्त एक उपयुक्त कदम है लेकिन प्रत्येक स्थिति पर सम्बन्धित क्षेत्र द्वारा ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

चंबल घाटी में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

2457. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चंबल घाटी की ऊबड़-खाबड़ भूमि को समतल करने का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किन-किन जिलों में कब प्रारंभ किया गया तथा 15 जून, 1994 तक कितना क्षेत्र समतल किया गया;

(ग) 15 जून, 1994 तक इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) क्या समतल की गई भूमि कृषि हेतु किसानों को आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां तो किन-किन शर्तों पर?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी, नहीं। कृषि मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

Availability of Foodgrains

2458. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the per capita availability of foodgrains by the year 2000 A.D. will be less than what it is today;

(b) what are the projections to indicate the availability of foodgrains per capita by the year 2000 A.D.; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (c) No, Sir. Given the projected rate of growth of population income and production, the per capita availability of foodgrains is expected to improve by 2000 A.D.

Plant Variety Bill

2459. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the status of the proposed "Plant Variety Bill" of 1993;

(b) whether it is a fact that the Bill has been referred to the Committee of Secretaries;

(c) what were the areas of differences with the Law Ministry; and

(d) the full details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) The proposal containing essential ingredients for Sui-Generis System of Protection of Plan Varieties is under finalisation in consultation with Ministry of Law as per the prescribed procedure. The proposal has been considered by the Committee of Secretaries.

(c) and (d) The Law Ministry had sought clarification on issues like proposed penal provision in the event of infringment, period of protection and duration of transition period etc. which has been furnished.

New Agricultural Policy

2460. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether new agricultural policy will create more employment and income opportunities in rural areas and tribal sectors; and

(b) the total out-put of foodgrains in the country during the last three years, year-wise and State-wise and against this output what was the demand and supply for the same period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Creation of gainful employment opportunities and generation of higher incomes in rural areas is the major objective of the Draft Agriculture Policy Resolution placed in Parliament on 14th May, 1993.

(b) The total output of foodgrains in the country during the last three years, year-wise and state-wise, is given in the enclosed statement. (*see* below) The demand for foodgrains largely depends upon factors like population, their income levels, prevailing price levels, availability of substitute food items, etc. During this period, the country was able to meet the demand for foodgrains from domestic production with marginal imports.

Statement

Estimate of Production of total foodgrains

State	Production (Thousand Tonnes)		
	1991-92	1992-93	1993-94 Anti-cipated (as on 13.6.94)
1	2	3	4
Andhra Pradesh	11705.4	11329.3	11618
Arunachal Pradesh	219.8	194.5	*
Assam	3379.2	3447.0	3533
Bihar	10638.4	9167.8	12451
Goa	147.1	150.1	*
Gujarat	3393.5	5409.7	3675